

प्रेषक,

ओम प्रकाश  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 13 जुलाई, 2015

विषय- उत्तराखण्ड राज्य हेतु "औषधि क्रय नीति"।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5प/1/52/2008-09/20627, दिनांक 17.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली-2008 दिनांक 01.05.2008 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2015, दिनांक 15.6.2015 से प्रवृत्त (आच्छादित) होने के कारण शासनादेश संख्या-1284/XXVIII-5/2008-24/2003 दिनांक 28.10.2009 के द्वारा चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए प्रख्यापित औषधि क्रय नीति सामयिक नहीं रह गयी है।

2- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली-2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के आलोक में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए औषधियों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन क्रय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा, जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी0ए0) द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की टर्न ओवर की प्रतियां ली जाए एवं उन्ही फर्मों से दवा की खरीद की जाए, जिनका विगत 03 वर्षों का औसत टर्नओवर कम से कम ₹ 70.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा, किन्तु रसायन (Chemical) के लिये ₹ 20.00 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय उत्पादकों को इस शर्त के साथ छूट देते हुये 03 वर्षों का औसतन टर्नओवर ₹ 20 करोड़ प्रतिवर्ष होगा। सर्जिकल आईटमों इत्यादि हेतु विगत 03 वर्षों का टर्नओवर ₹ 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा।
2. औषधियों का क्रय केवल उन्ही फर्मों से किया जाएगा, जिस फर्म के पास D.G.O.A. (रक्षा मंत्रालय) का अनुमोदन W.H.O.G.M.P./G.M.P. with Revised Schedule 'M'/G.M.P. with G.L.P.(Good Laboratory Practices) पंजीकरण प्रमाण-पत्र अवश्य हो। निर्माता फर्मों द्वारा अपनी निर्माण इकाई में स्थापित लैब से औषधि का उत्तम मानक कोटि का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदा में उल्लिखित औषधियों का निविदा फर्म का अपना उत्पादन व विक्रय का 03 वर्ष के अनुभव का प्रमाण-पत्र सी0ए0 से प्राप्त कर सम्बन्धित प्रान्त के औषधि नियन्त्रक द्वारा प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराया जाना होगा।
4. जिन औषधि आपूर्तिकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य डिपो/सी0एण्डएफ0 नहीं है, उनके फर्म द्वारा उत्पादित औषधि उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय वितरक से अनुबन्ध के उपरान्त ही उनके माध्यम से वितरण कर सकते हैं किन्तु बीजक उत्तराखण्ड राज्य का ही अन्तर्गत होगा।

5. किसी भी औषधि निर्माता की वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं वर्ष के वास्तविक उत्पादन में यदि अधिक अन्तर हो तो फर्म को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिये शासन को इस सम्बन्ध में इस शर्त को शिथिल करने का अधिकार होगा।
6. निविदादात्री फर्म अगर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधोमानक अथवा नकली दवा बनाने में दण्डित हुयी हो तो उस इकाई से औषधि का क्रय नहीं किया जायेगा। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा किसी अपराध में दण्डित हुयी हो तो तब भी फर्म से औषधि का क्रय न किया जाए।
7. प्रत्येक निविदादात्री फर्म को अपने लाईसेन्स की तथा उस पर अनुमोदित सारे औषधियों की अद्यतन सूची अपने प्रान्त के औषधि नियन्त्रक से सत्यापित कराते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।
8. कोई भी औषधि डी0पी0सी0ओ0 में प्रदत्त सीलिंग प्राइज से अधिक दर पर क्रय नहीं की जायेगी।
9. उत्तराखण्ड में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों से उनके द्वारा उत्पादित की गयी औषधियों को क्रय किये जाने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के अनुसार मूल्य वरीयता डी0पी0सी0ओ0 द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर्गत दी जायेगी।
10. उत्तराखण्ड की निर्माण इकाईयों के उत्पादकों के शासकीय क्रय के विषय में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश का अध्यारोही प्रभाव होगा।
11. प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर "यू0के0जी0 सप्लाय", "नॉट फार सेल" इन्डेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेशन ही मान्य होंगे। आयातित औषधियों/वैक्सीनों की सेल्फ लाइफ 50% स्वीकार होगी।
12. चिकित्सा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-291/XXVIII-4-2013-78/2012 दिनांक 05.03.2012 द्वारा प्रख्यापित आवश्यक औषधि सूची (इ0डी0एल0) में निहित औषधियों सर्जिकल सामग्री एवं नैदानिक सामग्री (Diagnostic) की ही निविदा की जायेगी।
13. चिकित्सा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-644/XXVIII-4-2014-28/2012, दिनांक 21.05.2014 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-50(9)/2010-पी.आई.-4, दिनांक 10.12.2013 में निहित 103 औषधियों का क्रय निर्धारित दर/न्यूनतम दर पर सी0पी0एस0यू0ई0 से निहित मार्गदर्शन के अनुरूप ही किया जायेगा।
14. भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियों को छोड़कर शेष समस्त औषधियों के टेण्डर कराये जायेंगे। हीमोफीलिया, एनटी रेबीज, एनटी स्नेक आदि औषधियों हेतु एक बार टेण्डर कराने पर यदि कोई निर्माता कम्पनी टेण्डर में प्रतिभाग नहीं करती है तो इन औषधियों की महत्ता/समयान्तर्गत उपलब्धता के दृष्टिगत ई0एस0आई0 की निर्धारित दरों पर शासन के पूर्वानुमोदन के पश्चात् क्रय की जा सकेंगी।
15. परिधिगत अधिकारियों द्वारा QUOTATION प्रक्रिया द्वारा कोई भी क्रय नहीं किया जायेगा, केवल आकस्मिकता यथा आपदा, बाढ़, दुर्घटना आदि परिस्थितियों में अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं संशोधित

स्थानीय क्रय भारत सरकार के उपक्रमों के साथ राज्य सरकारों के उपक्रमों को जो स्वयं औषधि निर्माता हों, से उक्त स्थिति में न्यूनतम दर पर औषधि क्रय की जा सकेगी, परन्तु इस हेतु क्रय किये जाने के लिए एक स्तर के ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन औचित्य के साथ प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

16. औषधि, रसायन, सर्जिकल सामग्री एवं अन्य नैदानिक सामग्री टैंडर हेतु निविदा पृथक से की जायेगी।
17. केन्द्रीय स्तर पर औषधियों का केवल मात्रा अनुबन्ध किया जायेगा।
18. एक बार में क्रय की गयी प्रत्येक औषधि के 20% दवाओं का रेण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाएगा ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच करायी जायेगी। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01-02 माह के भीतर सुनिश्चित की जायेगी।
19. प्रत्येक इस्तेमाल के अयोग्य घोषित आपूर्ति की गयी औषधियों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
20. क्रेता का आपूर्तिकर्ता फर्म के निर्माण एवं विश्लेषण व्यवस्था का निरीक्षण कराये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
21. यदि आपूर्ति की गयी सामग्री अधोमानक कोटी की पायी जाती है तो जांच में हुए व्यय को आपूर्तिकर्ता द्वारा ही वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस बीजक के अन्तर्गत आपूर्ति औषधि की कुल मात्रा की आपूर्ति पुनः की जानी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता, आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र होगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को, गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर, आपूर्ति न करने पर, औषधियों के अधोमानक होने पर अथवा किसी अन्य कमी के लिये ब्लैक लिस्ट एवं डिबार किया जा सकता है। डिबार अथवा ब्लैक लिस्ट की समय सीमा 03 वर्ष होगी। डिबार किये जाने की कार्यवाही शासन के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।
22. दरानुबन्ध एवं मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली औषधि की दरें राज्य में एक समान लागू होंगी।

राज्य स्तर पर औषधियों के क्रय हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

**(क) राज्य स्तरीय तकनीकी क्रय समिति।**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।  | अध्यक्ष      |
| 2. अपर निदेशक(चि0 उप0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।                                   | सदस्य        |
| 3. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।                               | सदस्य        |
| 4. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।  | सदस्य        |
| 5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, द्वारा नामित अन्य तकनीकी विशेषज्ञ। | सदस्य        |
| 6. संयुक्त निदेशक(भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।                                 | सदस्य/संयोजक |
| 7. महानिदेशक द्वारा नामित विशेषज्ञ (ई-प्रोकयोरमेन्ट)।   | सदस्य        |

**(ख) राज्य स्तरीय क्रय समिति।**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड। | अध्यक्ष |
| 2. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि।                  | सदस्य   |
| 3. चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि।               |         |

4. उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि। सदस्य
5. निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून। सदस्य
6. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। सदस्य
7. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। सदस्य
8. प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून। सदस्य
9. संयुक्त निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। सदस्य/संयोजक
10. महानिदेशक द्वारा नामित विशेषज्ञ (ई-प्रोक्योरमेंट) सदस्य

(ग) जिला स्तरीय क्रय समिति

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अध्यक्ष
  2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (भण्डार)। सदस्य/सचिव
  3. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सदस्य
  4. कोषाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। सदस्य
  5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय। सदस्य
  6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय। सदस्य
  7. चीफ फार्मासिस्ट, भण्डार। सदस्य
- संयोजक

समिति, दर अनुबंध, मात्रा अनुबंध व अन्य शर्तों के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी। उपरोक्त समितियों के लिए समिति के कुल 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में ही कोरम पूरा माना जायेगा, परन्तु वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि की अनिवार्यता बनी रहेगी।

23. प्रत्येक निविदा खुलने के पश्चात् टैक्स ढांचे में परिवर्तन यथा शासनादेश प्रभावी होगा।
24. निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उसका शुल्क आदि का निर्धारण महानिदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निविदाओं को ई-टेंडर के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा तथा ई-निविदा के अपलोड की तिथि को निविदा में उल्लिखित शर्तें जैसे स्पेसीफिकेशन, पंजीकरण एवं अन्य अभिलेख आदि पूर्ण होने चाहिये।
25. मात्रा अनुबंध व दर अनुबंध की शर्तें समान होगी।
26. ई-टेंडर से प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन ऑन-लाइन किया जायेगा तथा प्राप्त दरों को शासन द्वारा अनुमोदित कराया जाना होगा। मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत औषधि का क्रय समिति के अनुमोदन के उपरान्त विभागाध्यक्ष अपने वित्तीय अधिकारों की सीमा तक स्वयं कर सकेंगे तथा उससे अधिक के लिए शासन का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
27. ई-टेंडर से प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन ऑन-लाइन किया जायेगा। अर्नेष्ट मनी (धरोहर) एवं औषधियों के नमूने तकनीकी निविदा खुलने की निर्धारित तिथि व समय से पहले जमा कराये जाने होंगे।
28. प्रत्येक निविदादात्री फर्म से निविदा की अनुमानित लागत की धरोहर राशि (अर्नेष्ट मनी), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली-2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के अनुसार होगी, जिसे महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के नाम रहन किया जाना होगा, देय होगी। सरकार द्वारा निविदा-दात्री को बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी गयी धरोहर राशि (अर्नेष्ट मनी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। धरोहर राशि (अर्नेष्ट मनी) निविदा के सन्तोषजनक पूर्ण होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को लौटा दी जायेगी।



29. संविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा कुल धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जाएगी।
30. औषधियों के क्रय हेतु बजट की 70% धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा-स्वास्थ्य के निस्तारण पर रहेगी तथा 30% धनराशि का निस्तारण परिधिगत अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।
31. जिन औषधियों का रैंडम सैम्पल लिया गया है उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90% औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुंचने के 30 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10% धनराशि का भुगतान औषधि की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच आख्या आने के 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।
32. दो बार निविदा करने के पश्चात् यदि किसी औषधि, सर्जिकल सूचर, एक्स-रे फिल्म, सर्जिकल ग्लब्स, डिस्पोजेबल सीरिंज, आई0वी0 सैट, गॉज बैंडेज, काटन, मैकिनटोस, रबर शीट एवं अन्य सामग्री जो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, का क्रय ई0एस0आई0सी0 के दर अनुबन्ध की न्यूनतम दर से क्रय शासन के पूर्वानुमोदन से ही किया जा सकता है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-586/XXVII(7)/2015, दिनांक 09.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

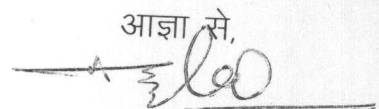
(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव

संख्या-932 (1)/XXVIII-4-2014-28(8)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. ~~औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।~~
11. समस्त सदस्यगण।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अनुर सिंह)